

## आतंकवाद का उन्मूलन

यह एडिटरियल 12/06/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Terror attack in Reasi underscores fragility of a hard-won peace in J&K" लेख पर आधारित है। इसमें रियासी में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के परिदृश्य में जारी सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर में भंगुर शांति के विषय में चर्चा की गई है।

### प्रलमिस के लिये:

[वधिविरुद्ध करिया-कलाप \(नवारण\) अधिनियम \(UAPA\) 1967](#), [राष्ट्रीय अनुवेषण अभिकरण \(NIA\) अधिनियम 2008](#), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राजनयिक एजेंटों सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन (1973), बंधक बनाने के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (1979), [आतंकी वित्तपोषण के दमन हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय \(1999\)](#), [वामपंथी उग्रवाद, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल](#)।

### मेन्स के लिये:

आतंकवाद के विभिन्न उभरते रूप, भारत के समक्ष आतंकवाद से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ।

**आतंकवाद** का साया पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। नागरिकों पर समन्वित हमलों से लेकर लक्षित हत्याओं तक, आतंकवादी समूह अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हिंसा और भय का इस्तेमाल करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद का मुकाबला करने की दृष्टि में प्रगति की है, लेकिन इसकी पहुँच और रणनीति अभी भी अस्थिर है, जो नरिंतर सतर्कता एवं अनुकूलन की आवश्यकता रखता है।

आतंकवाद से संघर्ष का लंबा इतिहास रखने वाले भारत को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर के अशांत क्षेत्र में यह विशेष रूप से प्रकट है, जहाँ रियासी ज़िले में तीर्थयात्रियों पर हाल ही में हुए हमले जैसी घटनाएँ शांति की भंगुरता को उजागर करती हैं। पूर्व में आतंकवाद से कम प्रभावित रहे रियासी जैसे ज़िले में ऐसी घटना का सामना आना क्षेत्र में शांति की भंगुरता को उजागर करता है।

**आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष** को बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। घुसपैठ के प्रयासों को रोकने और आतंकी नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिये कठोर सुरक्षा उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। केवल एक व्यापक रणनीति के माध्यम से ही, जिसमें सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ अंतरनिति शिकायतों को दूर करने के प्रयास शामिल हों, भारत अपने नागरिकों के लिये स्थायी शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति की उम्मीद कर सकता है।

## भारत में आतंकवाद से संबंधित ढाँचा

- **परिचय:** आतंकवाद हिंसा और धमकी का, विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध, मंशापूर्ण एवं अवैध उपयोग है, जिसका उद्देश्य भय पैदा करना और राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना है।
  - यह भय, व्यवधान और अनिश्चिता का माहौल बनाकर सरकारों या समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है।
  - भारत आतंकवाद के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' की नीति के साथ कठोर रुख रखता है।
  - हालाँकि आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, जिससे विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है।
    - यह असुस्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुँचाती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने में सक्षम बनाती है।
- **घरेलू कानून:**
  - [वधिविरुद्ध करिया-कलाप \(नवारण\) अधिनियम \(UAPA\), 1967](#): यह आतंकवादी संगठनों या व्यक्तियों को नरिदषित करता है, आतंकवादी गतिविधियों को आपराधिक घोषित करता है और जाँच एवं अभियोजन के लिये अधिकारियों को सशक्त बनाता है।
  - [राष्ट्रीय अनुवेषण अभिकरण \(NIA\) अधिनियम, 2008](#): यह आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच एवं अभियोजन के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना करता है।
- **संस्थागत ढाँचा:**
  - [राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय \(NSCS\)](#): राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकी देखरेख एवं समन्वय करता है जिसमें आतंकवाद-रोधी

प्रयास भी शामिल हैं।

- गृह मंत्रालय (MHA): घरेलू स्तर पर आतंकवाद वरिधी अभियानों और खुफिया सूचना संग्रहण का नेतृत्व करता है।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA): यह आतंकवाद-संबंधी बड़े मामलों की जाँच और अभियोजन में भूमिका निभाता है।
- अंतरराष्ट्रीय समझौते: भारत आतंकवाद-रोधी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है, जिनमें शामिल हैं:
  - राजनयिक एजेंटों सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के वरिद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of Offences against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents), 1973
  - बंधकों बनाने के वरिद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (International Convention against the Taking of Hostages), 1979
  - आतंकी वित्तपोषण के दमन हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism), 1999

## आतंकवाद के विभिन्न उभरते रूप कौन-से हैं?

- 'लोन वुल्फ' हमले (Lone Wolf Attacks): ऐसे कट्टरपंथियों का उभार हुआ है जो किसी बड़े समूह का अंग हुए बिना स्वयं के स्तर पर हमले कर रहे हैं, जो खुफिया एजेंसियों के लिये एक बड़ी चुनौती बन गई है।
  - इन 'लोन वुल्फ' आतंकवादियों का पता लगाना कठिन होता है और वे बिना किसी चेतावनी के भी हमला कर सकते हैं।
- जैव आतंकवाद संबंधी जोखिम: कोविड-19 महामारी ने जैव आतंकी हमले की संभावना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जहाँ बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिये वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जैविक वषिकृत पदार्थों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - वनिशकारी मंशा रखने वाले अराजक तत्त्वों द्वारा ऐसे जैव एजेंटों की अवैध खरीद एवं तैनाती एक बड़ा खतरा बनी हुई है, जसि पर नरितर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
- मानवरहित यान/ड्रोन संबंधी खतरे: उन्नत लेकिन सस्ती वाणजियकि ड्रोन प्रौद्योगिकियों के तीव्र प्रसार ने एक नए खतरे का द्वार खोल दिया है, जहाँ आतंकवादी खुफिया सूचना संग्रहण, लक्षित हमलों या वसिफोटकों/रासायनिक प्रसरण उपकरणों के वरिणर प्लेटफॉर्म के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे एक नई सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुई है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने जून 2021 में जममू में वायु सेना स्टेशन पर एक गंभीर ड्रोन हमले का सामना किया।
  - भारत-पाकसिातान सीमा से 14 किलोमीटर दूर स्थिति इस एयरबेस पर लो-फ्लाईंग ड्रोनों द्वारा हमला किया गया, जहाँ एयरबेस पर दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डेवाइस (IEDs) गरिए गए।
- आतंकवादियों के सुरक्षा ठिकाने: अफ्रीका और मध्य-पूर्व के कुछ भू-भागों में लंबे समय से संघर्षग्रस्त एवं सीमति शासन वाले संवेदनशील क्षेत्र आतंकवादी समूहों को सुरक्षा आश्रय पाने, प्रशिक्षण अवसरचनाएँ स्थापति करने और सीमा-पार हसिा फैलाने के लिये अनुकूल आधार प्रदान करते हैं, जसिसे ये अस्थिर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिये सहायक बन जाते हैं।
- आतंकवाद-अपराध गठजोड: आतंकवादी समूहों और अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक सडिकिट के बीच गहराता अभसिणर उनके अ्रिध वरितीय संसाधनों (करपिटोकरेंसी के माध्यम से), वरिणर नेटवरक (जैसे पंजाब में नशीली दवाओं का आपूर्ति तंत्र) और हथियारों की खरीद एवं मानव तस्करी जैसे क्षेत्रों में वशिषज्जता के साथ संयुक्त होकर एक शक्तिशाली खतरा गुणक के रूप में उभरा है जो नरितर आतंकवाद वरिधी अभियानों की मांग रखता है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रेरित आतंकवाद: आतंकवादी समूह भरती, कट्टरपंथ के प्रसार, अभियान संबंधी योजना-नरिमाण और हमले के नषिपादन के सभी चरणों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये एनकरपिटेट संचार एवं डारक वेब जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
  - आतंकवाद-रोधी बलों के लिये इस प्रौद्योगिकीय वकर से आगे बने रहना एक सतत् चुनौती बनी हुई है।

## भारत के समक्ष वरिद्यमान आतंकवाद संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

- सीमा-पार आतंकवाद: भारत अपने पड़ोसी देशों, वशिषकर पाकसिातान की ओर से, सीमा-पार आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है।
  - हाल के घटनाक्रमों में वर्ष 2019 का पुलवामा हमला शामिल है, जहाँ पाकसिातान स्थिति आतंकवादी समूह के एक आत्मघाती हमलावर ने भारतीय सुरक्षाकरमियों के काफलि को नशिाना बनाया था।
  - अभी हाल में रयासी (जून 2024) में तीरथयात्रियों पर हमले जैसी घटनाओं से उजागर होता है करिाजौरी और पुंछ जैसे पारंपरिक रूप से आतंकवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा दबाव बढ़ने से अब आतंकवादी परधीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE): वामपंथी उग्रवाद आंदोलन, जसि नक्सलवादी वरिरोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के लिये एक सतत् चुनौती रहा है।
  - माओवादी वरिरोही समूह छत्तीसगढ और झारखंड जैसे कई राज्यों में सक्रिय हैं, जो हसिा, जबरन वसूली और वकिसा परयोजनाओं में बाधा डालने में संलपित हैं।
  - वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हसिक घटनाओं की संख्या में 76% की कमी आई है।
  - हालाँकि यह समस्या अभी भी बनी हुई है, जसिकी पुष्टि हाल ही में छत्तीसगढ के नारायणपुर जिले में हुई घटना से होती है।
- अलगाववादी आंदोलन और आतंकवाद: भारत को पूर्वोत्तर और पंजाब सहित विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों और आतंकवाद का सामना करना पडा है।
  - जममू-कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा वशिष रूप से जटलि रहा है, जहाँ लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे पाकसिातान स्थिति आतंकवादी समूह इसे हवा दे रहे हैं।
- कट्टरपंथ का प्रसार और ऑनलाइन प्रोपेगंडा: कट्टरपंथ का उभार (वशिष रूप से युवाओं में) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चरमपंथी वरिचारधाराओं का प्रसार एक गंभीर चुनौती है।
  - भारत में युवाओं को 'हनी ट्रैपिंग' (जैसे हाल ही में पूर्व बरहमोस इंजीनियर को लुभाने का मामला) जैसे तरीकों से कट्टरपंथी बनाये जाने

और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती किये जाने के कई उदाहरण देखे गए हैं।

- **फरवरी 2024** में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मामले में **NIA** ने 4 लोगों को गरिफ्तार किया था।

- **साइबर आतंकवाद:** डिजिटल अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता और आतंकवादी समूहों या राज्य प्रायोजित अभिकर्ताओं द्वारा साइबर हमलों की संभावना भारत के लिये एक उभरती हुई चिंता है।
  - साइबर आतंकवाद **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय प्रणालियों और संवेदनशील डेटा** को नशाना बना सकता है, जिससे महत्त्वपूर्ण व्यवधान एवं आर्थिक क्षति की स्थिति बन सकती है।
  - हाल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की एक कंपनी ने लगभग **100 गीगाबाइट भारतीय आवरण डेटा** का उल्लंघन किया है।
- **पाकिस्तान का FATF के 'ग्रे लसिट' से बाहर आना:** चूँकि पाकिस्तान को FATF के 'ग्रे लसिट' से बाहर कर दिया गया है, आतंकवादी समूहों के वरिद्ध पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के अभाव का भारतीय दावा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतने महत्त्व से नहीं देखा जाएगा।
  - **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की सूची में पाकिस्तान को शामिल किये जाने से भारत की चिंताओं की एक प्रकार से पुष्टि हुई थी।
  - इसके अलावा, इस मामले में 'चाइना फैंक्टर' भी सामने आता है, जो हाफजि सईद को आतंकवादी घोषित करने की भारत की मांग को चीन द्वारा अवरुद्ध करने से उजागर होता है।

## आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

- **केवल दंड पर नहीं, बल्कि पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करना:** कट्टरपंथ के प्रारंभिक चरण में पाए गए व्यक्तियों के लिये कट्टरपंथ मुक्ति कार्यक्रम विकसित किये जाएँ।
  - इन कार्यक्रमों को कट्टरपंथ के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिये और प्रतभागियों को पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।
- **राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी डेटाबेस की स्थापना करना:** एक ऐसा केंद्रीकृत एवं सुरक्षित डाटाबेस विकसित किया जाए जो कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों सहित **वभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचना को एकीकृत** करता हो।
  - पैटर्न, कनेक्शन एवं संभावित खतरों की पहचान करने के लिये **उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग** तकनीकों का लाभ उठाया जाए, ताकि अग्रसरकिये कार्रवाई संभव हो सके।
- **भौतिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि करना:** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, सार्वजनिक स्थानों और संभावित उच्च जोखिमियुक्त लक्ष्यों के लिये भौतिक सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए, जिसमें **नगरानी प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण और परधि सुरक्षा** शामिल है।
  - संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिये नियमित **सुरक्षा ऑडिट एवं भेद्यता आकलन** का आयोजन किया जाए।
  - आतंकवादी हमलों की स्थिति में प्रबल **संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल** और बचाव-निकासी योजनाओं (evacuation plans) को लागू किया जाए।
- **पुलिस के लिये ओपन-सोर्स इंटेलेजेंस प्रशिक्षण:** संभावित खतरों की पहचान करने और आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मंचों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने हेतु **ओपन-सोर्स इंटेलेजेंस (OSINT) प्रौद्योगिकियों** में पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाए।
- **साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना:** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना और ऑनलाइन प्रणालियों को आतंकवादी संगठनों के साइबर हमलों एवं **डिजिटल जासूसी** से बचाने के लिये उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों के विकास में नविश किया जाए।
- **सुरक्षा बलों के साथ ही समुदायों को भी सशक्त बनाना:** समुदायों को, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, **कट्टरपंथ के आरंभिक संकेतों और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में** शक्ति करने की आवश्यकता है।
  - चरमपंथी प्रभाव के प्रती संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का समाधान किया जाए। आशा की भावना पैदा करने और कट्टरपंथ को हतोत्साहित करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं आजीविका के अवसरों में सुधार लाया जाए।
  - जम्मू-कश्मीर में **'हिमायत' (Himayat) और 'उम्मीद' (UMEED) योजना** इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - युवाओं को नई दिशा प्रदान करने के साधन के रूप में कट्टरपंथ की संभावना वाले क्षेत्रों में **'खेलो इंडिया सेंटर'** स्थापित किये जा सकते हैं।
  - **आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाना** और इस प्रकार उनके **मन-मसतषिक को जीतना** आवश्यक है। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में संबंधित बैठक का आयोजन इसी दिशा में उठाया गया कदम था।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को साझा उत्तरदायित्व के रूप में** बढ़ावा देने का यह उपयुक्त समय है।
- **आतंक की वित्तीय जीवनरेखा को कमजोर करना:** वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।
  - ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता के कारण आतंकवादियों के लिये धन स्थानांतरित करना कठिन सिद्ध हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत के समक्ष वभिन्न उभरते आतंकवादी खतरों की चर्चा कीजिये। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इन चुनौतियों के प्रभाव के शमन के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. 'हैड-इन-हैड 2007' संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सेना के अधिकारियों और नमिनलखिति में से कसि देश की सेना के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था? (2008)

- (a) चीन
- (b) जापान
- (c) रूस
- (d) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (a)

**??????:**

प्रश्न. आतंकवाद की महावपित्तराष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट के नियंत्रण के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं? आतंकी नधियिन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dismantling-the-roots-of-terrorism>

